

CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

पशुपालन विभाग जम्मू ने पहली बार पशु-मंडी का उद्घाटन किया



दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए, पशुपालन विभाग जम्मू ने सरकारी पशु/भेड़पालन एवं मत्स्य पालन विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में आज आरपी चैक पोस्ट, लखनपुर (कठुआ) जम्मू-कश्मीर क्षेत्र संघ में पहली बार पशु-मंडी का आयोजन किया।

निदेशक पशुपालन जम्मू डॉ. सागर डी. डोईफोड ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने डेयरी किसानों और प्रजनकों को अवगत कराया कि जिला प्रशासन कठुआ के सक्रिय सहयोग से विभाग द्वारा यह पहली तरह की पहल है।

पड़ोसी राज्यों से प्रजनकों/विक्रेताओं द्वारा लगभग 400 अच्छी गुणवत्ता वाले मवेशी/भैंस लाए गए थे। कार्यक्रम में स्थानीय डेयरी किसान विशेष रूप से 'एकीकृत डेयरी विकास योजना' के लाभार्थी अपनी पसंद के पशु खरीदते देखे गए।

झारखंड के डेयरी किसानों को मादा बछड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए जल्द मिलेगा 'सेक्सड सीमेन'



झारखंड में दुग्ध किसान जल्द ही वीर्य का एक पैकेट चुनने में सक्षम होंगे जो मादा बछड़े के जन्म को सुनिश्चित करेगा, जिससे नर बछड़े या बैल को पालने का बोझ कम हो जाएगा जो कि खेती में नहीं रहने वालों के लिए बेकार हो जाता है। राज्य के पशुपालन विभाग के तहत झारखंड मिल्क फेडरेशन (जेएमएफ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एक समझौता करने के लिए तैयार है, जिसने पिछले साल स्वदेशी रूप से यौन वीर्य की कृत्रिम गर्भाधान (एआई) तकनीक विकसित की है जो मादा बछड़े के जन्म को सुनिश्चित करती है।

राज्य के कृषि और पशुपालन सचिव अबूबकर सिद्दीक ने कहा कि राज्य 31 मार्च, 2024 से पहले एनडीडीबी के साथ एक नए एमओयू पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। "एनडीडीबी के अधिकारी अगले 10 दिनों में सेक्सड सीमेन से जुड़ी नई एआई तकनीक और एक श्रृंखला के बारे में एक प्रस्तुति देंगे इसके अलावा किसानों के लिए एआई केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

दैनिक दूध उत्पादन को 10 लाख लीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य: असम के मंत्री अतुल बोरा



असम के पशुपालन मंत्री अतुल बोरा ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध के उत्पादन पर जोर दिया है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित योजना के साथ राज्य के डेयरी क्षेत्र का नेतृत्व करने का प्रयास किया गया है। बोरा ने बताया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और असम सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

डेयरी विकास निदेशालय में आठ नवनियुक्त डेयरी प्रौद्योगिकीविदों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए अतुल बोरा ने कहा, "केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में सोमवार 1 दिसंबर, 2021 को गुवाहाटी के खानापारा में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।"

केरल किसान कल्याण कोष बोर्ड अब ऑनलाइन उपलब्ध है

किसान अब केरल किसान कल्याण कोष बोर्ड में सदस्यता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। कृषि मंत्री पी. प्रसाद ने बुधवार को ऑनलाइन सुविधा का उद्घाटन किया, जिसे kfwfb.kerala.gov.in पर देखा जा सकता है।

18 से 55 वर्ष की आयु के किसान सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य शर्तों में शामिल हैं; उनके पास कम से कम पांच सेंट भूमि होनी चाहिए लेकिन 15 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। उनकी वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, आजीविका का प्रमुख साधन कम से कम तीन साल से खेती होना चाहिए। 20 दिसंबर, 2019 तक 56 वर्ष की आयु वाले किसान - जिस तारीख को केरल किसान कल्याण कोष अधिनियम प्रभावी हुआ, 65 वर्ष की आयु तक सदस्य के रूप में जारी रह सकते हैं।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, जलीय कृषि, रेशम उत्पादन, सजावटी मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती और बटेर पालन में लगे लोग आवेदन करने के लिए पात्र हैं। न्यूनतम मासिक प्रीमियम ₹100 है, लेकिन अधिक राशि प्रेषित की जा सकती है। सरकार सदस्यों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम से मेल खाने वाली मासिक राशि भेजेगी, जो अधिकतम ₹250 के अधीन होगी।

एक बार जब कोई किसान 60 वर्ष का हो जाता है, तो वह प्रेषित प्रीमियम के अनुरूप पेंशन का हकदार होगा। चिकित्सा सहायता के अलावा, कल्याण कोष उन सदस्यों को पारिवारिक पेंशन, मृत्यु लाभ और वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो बीमारियों या दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता को बनाए रखते हैं।



KERALA GOVT SETS UP WELFARE BOARD FOR FARMERS

डॉ वर्गीज कुरियन की शताब्दी पर 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' मनाने के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए

डॉ. वर्गीस कुरियन की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस समारोह के दौरान केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपला देशी गाय/भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान विजेता, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/ दुग्ध उत्पादक कंपनी/ डेयरी किसान उत्पादक संगठन के विजेताओं को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।

पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा स्वदेशी गोजातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से वर्ष 2014 में राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत "राष्ट्रीय गोकुल मिशन" की शुरूआत की गई थी।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं और भैंसों का आनुवांशिक सुधार करना है। योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसानों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और डेयरी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है।

इसमें विभाग द्वारा अलग-अलग श्रेणी का निर्धारण किया गया है, यह श्रेणियां इस प्रकार है:-

1. देशी गाय/भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान,
2. सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) और
3. सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/ दुग्ध उत्पादक कंपनी/ डेयरी किसान उत्पादक संघ

प्राप्त आवेदनों में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार के रूप में योग्यता प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह एवं राशि प्रदान की गई जो इस प्रकार है:- 1) 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) – प्रथम स्थान, 2) 3,00,000 रुपये (तीन लाख रुपये) – द्वितीय स्थान, 3) 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) – तीसरे स्थान के लिए



कॉर्नेक्सट: यह स्टार्टअप डेयरी किसानों के लिए चारा संकट का समाधान करता है

2015 में तीन उद्यमियों- माधव क्षत्रिय, अमरनाथ सारंगुला और फिरोज अहमद द्वारा स्थापित- कॉर्नेक्सट ने डेयरी किसानों की मदद के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। यह एग्रीटेक स्टार्टअप डेयरी किसानों के लिए कम लागत, अभिनव गुणवत्ता वाले फीडिंग समाधान प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया से एमबीए और खुद डेयरी किसान क्षत्रिय को एक डेयरी किसान के दर्द की गहरी समझ है। सारंगुला, रणनीतिक योजना में अनुभव के साथ एक आईआईटीयन, विकेन्द्रीकृत ग्रामीण उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मालिकाना संतुलन प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है। लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अहमद कम-मूल्य-उच्च-वॉल्यूम लॉजिस्टिक्स में नवीनता लाते हैं।



हाल ही में, कॉर्नेक्सट स्टार्टअप नेशन सेंट्रल, इज़राइल, टीआईआई हैदराबाद और टीआईआई इज़राइल द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए 'इंडो इज़राइल कोहोर्ट प्रोग्राम' के लिए भारत से चुने गए सात स्टार्टअप में से एक बन गया। कॉर्नेक्सट के सीईओ क्षत्रिय ने कहा, "हमारा लक्ष्य भारत में डेयरी किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण चारा आसानी से उपलब्ध कराना है।"

कॉर्नेक्सट भारतीय डेयरी किसानों की मदद के लिए एक चारा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत सिलेज बेलिंग नामक एक विघटनकारी तकनीक से हुई, जो स्वाभाविक रूप से किण्वित, अत्यधिक पौष्टिक, खाने के लिए तैयार हरा चारा है, जिसे आयातित तकनीक का उपयोग करके सिलेज बेल्स के रूप में पैक किया जाता है। कॉर्नेक्सट जल्द ही अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप "फीडनेक्सट" लॉन्च कर रहा है, जो डेयरी को कम लागत वाले गुणवत्ता वाले फीडिंग समाधान प्रदान करता है जैसे कि बाल्ड साइलेज, टीएमआर (कुल मिश्रित राशन), फोर्टिफाइड घास, खनिज मिश्रण, फीड सप्लीमेंट आदि। किसान। नया ई-मार्केटप्लेस 'फीडनेक्सट' डेयरियों की सभी खाद्य आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप शॉप होगा।

किसानों को जैविक तरीके से आगे बढ़ाएं, अमित शाह ने अमूल से कहा, नई सुविधाओं का उद्घाटन किया



केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में अमूलफेड डेयरी की चार नई सुविधाओं का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए, उर्वरक आधारित खेती के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए आवश्यक बताते हुए, इस संबंध में अमूल के निदेशक मंडल से अनुरोध किया। मिल्क पाउडर फैक्ट्री, बटर प्लांट, रोबोट हाई-टेक वेयरहाउसिंग फैसिलिटी और पॉली फिल्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सहित सुविधाओं पर 415 करोड़ रुपये की लागत आई है।

अमूलफेड डेयरी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) का एक हिस्सा है, जो गुजरात में डेयरी सहकारी

समितियों के लिए शीर्ष राज्य स्तरीय मार्केटिंग फेडरेशन है, जो अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करता है। शाह ने कहा कि गुजरात में दो लाख से अधिक किसानों ने जैविक खेती करना शुरू कर दिया है और उत्पादकता में वृद्धि और कम पानी की आवश्यकता के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि अमूल नए क्षेत्रों में उद्यम कर सकता है।

मंत्री ने कहा कि एक बैठक में, अमूल के निदेशक मंडल ने उन्हें जैविक कृषि उत्पादों की मदद के लिए पहल पर एक प्रस्तुति दिखाई थी। उन्होंने कहा, 'इसमें पैसा लगाने की जरूरत है। अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो एक योजना लेकर आएँ और हम सब प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। केंद्र सरकार निश्चित रूप से मदद करेगी,' शाह ने कहा।